



उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद,

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक: — /रा0उ0शि0प0 / — / —
दिनांक 03 अगस्त, 2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन/सदस्य सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय:— विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के NAAC संस्था से मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन का आधार सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं के NAAC संस्था से मूल्यांकन कराकर अच्छी ग्रेडिंग (A,B,C) प्राप्त करना है। NAAC संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चयन एवं मापदण्ड निर्धारण का कार्य किया जाता है। राज्य सरकार का अभिमत है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के वृद्धि तभी सम्भव है जबकि शिक्षण संस्थाएँ, गुणवत्ता आकलन की पात्रता में अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या:— D.O. No.12-24/2012-U.1, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा (प्रति संलग्न) भी आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं (राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों) का NAAC संस्था से मूल्यांकन

कराये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये एक लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)

अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव

पृ0सं0- १६ /रा0उ0शि0प0 / ०२/ 15^{तददिनांक}।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को इस निदेश के साथ कि वह कृपया विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध समस्त शिक्षण संस्थाओं को NAAC संस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराये।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस निदेश के साथ कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली उच्च शिक्षण संस्थाओं के लक्ष्य निर्धारित करते हुये मूल्यांकन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने हेतु निर्देशित करें एवं पात्रता क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं की सूचना अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद के E-mail:upshec@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।
3. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- ✓ 4. नैक/आई0क्यू0ए0सी0, कोआडिनेटर्स, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।



डा0(आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव



अशोक ठाकुर
सचिव
ASHOK THAKUR
SECRETARY

सचिव, उच्च शिक्षा

No. 692 / MS/GI/2013

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Higher Education

25-1-2013
(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

VS(Am)

सं. 6117 / पी.एस. / सचिव / उ०शि०/2013

दिनांक 31/1/2013

D.O. No. 12-24/2012-U.1

Dated the 18th January, 2013.

30/1/13

16(5)/13
SL-1

Dear Shri Jawed Usmani,

You may be aware that the process of accreditation enables recognition of Higher Educational institutions (HEIs) as conforming to parameters of academic quality and benchmarks determined by the regulatory authority.

2. Accreditation of HEIs has the following benefits:

- Enables an institution to know its strengths, weaknesses and opportunities, through an informed review process undertaken by a third party, to augment its quality.
- Makes available reliable data, relating to compliance with quality parameters, to all the stakeholders (students/government/funding agencies/employers etc.) as inputs in their decision making process.
- Fosters innovation and adoption of best practices.
- Encourages intra and inter-institutional interactions.

3. Presently accreditation is voluntary; as a result of which less than one-fifth of the colleges and less than one-third of all universities have obtained accreditation. Mandatory accreditation in the higher education, would enable the higher education system in the country to become a part of the global quality assurance system and reap the associated benefits.

4. The University Grants Commission (UGC) has finalized the Regulations on mandatory assessment and accreditation of HEIs. These Regulations would cover all universities under a Central / State Act, all Deemed to be Universities (other than technical institutions) and all colleges (other than technical institutions). A copy of the UGC Regulation is enclosed. This Regulation has already been sent by UGC for notification in the Gazette. The AICTE is also separately notifying similar Regulations for technical institutions other than universities.

5. The UGC Regulations stipulate mandatory assessment and accreditation of HEIs as pre-requisites for funding/ recognition by UGC, prescribe the time schedules for undergoing accreditation/ re-accreditation, designate Accreditation Agencies and the penal provisions for not complying with these Regulations.

654/VS/m/13
JS (Am)
अमिता अग्रवाल
31.1/13
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश सचिवालय।

रजनीश
श्री साहू
श्री बिप्लव
25-1-2013
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
हजे
01-2-13

मुख्य सचिव के शास (06-3)
उ०शि०
30-1-13
1-2-13
सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

128 C Wing, Shastri Bhavan, New Delhi - 110 115
Tel. : 23386451, 23382698 Fax : 23385807
E-mail : secy.dhe@nic.in, ashokthakur54@gmail.com

6. Since the mandatory accreditation has to be done in the stipulated time frame, this Ministry is taking measures to expand the capacity of existing Accreditation Agencies i.e. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and National Board of Accreditation (NBA) and has also requested Ministries of Health and Family Welfare, Law & Justice/ Department of Agricultural Research and Education and School Education to set up new Accreditation Agencies. A note in this regard is also enclosed.

7. **Necessary support and guidance for setting up such agencies will be available from NAAC and NBA. Mandatory Accreditation can also be adopted as one of the norms for deciding state funding/ intervention in a particular State Higher Educational Institution.**

During the process of consultations with states on National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions (NARAHEI) Bill, many states had expressed the desire to create their own accreditation agencies.

8. It is requested to initially familiarize the State Higher Educational Institutions with the need to undergo assessment and accreditation and subsequently to monitor them in their efforts to undergo these processes. A workshop with the Chief Secretaries/ representatives of States/UTs will also be convened by this Ministry, On 6th March, 2013 to consolidate efforts for successful introduction of the regime of mandatory accreditation of Higher Educational Institutions.

With regards,

Yours sincerely,



(Ashok Thakur)

Encl: As stated above.

Shri Jawed Usmani,
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lal Bahadur Shastri Bhawan
Lucknow- 226 001.